

पत्र क्रमांक 9197-स०क०-१-७३/२२५६७-६७०

प्रेषक

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

१. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी (ना०)।

२. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, पंजाब तथा हरियाणा, चण्डीगढ़ और हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश।

दिनांक चण्डीगढ़, १८ दिसम्बर, १९७३।

विषय :——अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए २० प्रतिशत तथा पिछड़े वर्ग के लिए २ प्रतिशत आरक्षण।

महोदय;

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक ६०७६-स०क०-१-७२/१५५९४-६९३, दिनांक १५ सितम्बर, १९७२ द्वारा जारी की गई हिवायतों की ओर दिलाऊं और कहूँ कि इस मामले की जांच की है तथा यह निर्णय लिया गया है कि जो अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारी हरियाणा सरकार की सेवा में हैं उन्हें भी बोनाफाईड रैसीडेंट्स आफ हरियाणा (bonafide residents of Haryana) माना जाना चाहिए और उन्हें तथा उनके वर्चों को इन वर्गों के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।

भवदीय,

सुशील जैन

उप-सचिव,

कृते: आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
समाज कल्याण विभाग।

दिनांक चण्डीगढ़ १८-१२-१९७३

क्रमांक ९१९७-स० क०-१-७३/२२६७